चीन का कार्बन बाजार

❖ हालिया संदर्भ :

- चीन 2024 के अंत तक कार्बन उत्सर्जन व्यापार योजना (ETS) में सीमेंट, स्टील एवं एल्यूमिनियम उत्पादन को शामिल किए जाने की योजना पर जनता से प्रतिक्रिया मांग रहा है, क्योंकि चीन को उम्मीद है कि ऐसा करने से बाजार में तरलता में वृद्धि हो सकती है।

❖ चीन का कार्बन बाजार :

- चीन के कार्बन बाजार में दो प्रकार की प्रणालियाँ है, जिसमें एक ETS एवं दूसरा स्वैच्छिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कटौती व्यापार बाजार है।
- इसे संयुक्त रूप से चीन प्रमाणित उत्सर्जन कटौती (CCER) योजना भी कहा जाता है, जिसे 2024 के शुरूआत में संशोधित किया गया था।
- ETS में चीन के 8 प्रमुख उत्सर्जन क्षेत्र-बिजली उत्पादन, स्टील निर्माण सामग्री, पेट्रोलियम, नागरिक उड्डयन, अलौह धातु, रसायन एवं कागज उद्योग शामिल है, जो चीन के कुल उत्सर्जन में 75% का योगदान देते हैं।

❖ ETS :

- इस अनिवार्य कार्बन बाजार ने जुलाई 2021 में शंघाई पर्यावरण एवं ऊर्जा एक्सचेंज पर अपना कारोबार प्रारंभ किया।
- पहले चरण के दौरान इसमें बिजली क्षेत्र के 2000 प्रमुख उत्सर्जक शामिल हुए, जिनका वार्षिक उत्सर्जन न्यूनतम 26000 मीट्रि टन है।
- भविष्य में शामिल होने वाले स्टील, एल्यूमिनियम एवं सीमेंट क्षेत्र के लिये भी न्यूनतम उत्सर्जन सीमा यही रहेगी।
- इस प्रणाली के तहत प्रत्येक उत्सर्जक को मुफ्त प्रमाणित उत्सर्जन अनुमतियों (CEA) का कोटा दिया जाता है।
- यदि कोई उत्सर्जक निर्धारित CEA से ज्यादा उत्सर्जन करता है तो उसे बाजार से अतिरिक्त CEA खरीदना पडता है और यदि कोई उत्सर्जक निर्धारित सीमा से कम उत्सर्जन करता है तो उसे अपना अधिशेष CEA बाजार में बेचने की अनुमति होती है।
- CEA का निर्धारण सरकार द्वारा उद्योग कार्बन तीव्रता बेंचमार्क के आधार पर किया जाता है।

- उत्सर्जक मासिक आधार पर प्रमुख पैरामीटर प्रस्तुत करने एवं वार्षिक आधार पर उत्सर्जन की डेटा-रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिये बाध्य होते हैं।

❖ विस्तार :

- स्थापना के बाद से यह दुनिया का सबसे बडा कार्बन-बाजार बन गया है।
- चीन का कार्बन बाजार लगभग 5.1 बिलियन टन Co_2 के बराबर है, जो चीन के कुल उत्सर्जन का लगभग 40% है।
- आँकडों के अनुसार 2023 तक ETS पर कार्बन-व्यापार की मात्रा लगभग 25 बिलियन युआन (चीनी मुद्रा) के बराबर था।
- 3 नए संभावित क्षेत्रों को शामिल कर लिये जाने के बाद ETS के दायरे में 1500 नए उत्सर्जक शामिल हो जाएंगे, जिससे 3 बिलियन टन Co_2 व्यापार में जुड जाएगा, जिससे कार्बन-क्रेडिट की मांग और कीमत दोनों बढेगी।

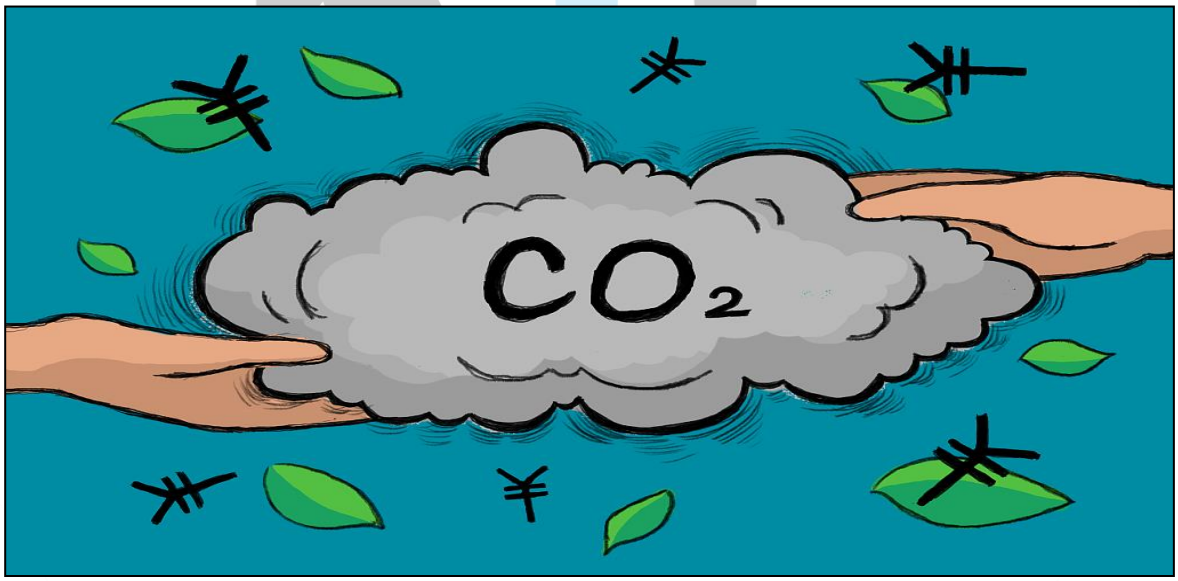

❖ अवधारणा की शुरूआत :

- क्योटो प्रोटोकॉल (1997) के तहत, जो पेरिस समझौता (2015) का पूर्ववर्ती है, कार्बन-बाजार की अवधारणा शुरू हुई।
- दरअसल क्योटो प्रोटोकॉल, जो 2005 में लागू हुआ, ने विकसित देशों के समूह पर कार्बन-उत्सर्जन की सीमा तय कर दी थी।
- अन्य देशों के लिये ऐसी कोई बाध्यता नहीं थी, लेकिन अगर ये देश कम कार्बन-उत्सर्जित करते तो उन्हें कार्बन-क्रेडिट प्राप्त होता और वे उसे विकसित देशों को बेच सकते थे अगर विकसित देश तय सीमा से ज्यादा कार्बन उत्सर्जित करते।
- कम-मांग के कारण कार्बन-बाजार प्रभावी नहीं रहा।